यूपी को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में जुटें विभाग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा-महाकुंभ के आयोजन से प्रदेश की जीडीपी में आएगा बड़ा उछाल

- सरकार के आठ वर्ष पूरे होने पर लेंगे तीन दिवसीय कार्यक्रम
- अधिकारी सप्ताह के अंत में फिल्ड विजिट पर निकलें
- मुख्यमंत्री ने कहा-आम जनता की सुविधा शीर्ष प्राथमिकता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अपने सरकारी आवास पर समीक्षा बैठक करते ● सूचना विभाग

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डालर तक ले जाने के लक्ष्य के लिए अब तक हुए प्रयासों और परिणामों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य बड़ा है, हर विभाग जिम्मेदारी निभाए। अधिकारियों से कहा कि सप्ताह के अंत में फील्ड विजिट पर निकलें। फील्ड के अधिकारियों को अनावश्यक राज्य मुख्यालय न बुलाएं।

मुख्यमंत्री आवास पर शाम को आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 मार्च को वर्तमान सरकार के आठ वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह आठ वर्ष नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के सृजन के रहे हैं। आठ वर्ष पूरे होने के अवसर पर सभी जिलों में तीन दिवसीय मेले का आयोजन किया जाए। इन मेलों में केंद्र सरकार द्वारा पिछले 11 वर्षों और राज्य सरकार द्वारा आठ वर्षों में जनता की सेवा, सुरक्षा और प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए किए गए प्रयासों और परिणामों से जनता को अवगत कराने का इंतजाम करें। विभाग अपनी उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाएं। शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। तीन दिवसीय मेलों में लोककल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को इसका लाभ दिलाया जाए। सभी जिलों में यह कार्यक्रम किया जाना है। सभी आवश्यक कार्यवाही समय से पूरी कर ली जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ के आर्थिक प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। महाकुंभ प्रयागराज के आयोजन ने प्रदेश के हास्पिटैलिटी, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बड़ा बूस्ट दिया है। अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा है। इस साल राज्य की जीडीपी में बड़ा उछाल आएगा। जीडीपी के अंतिम आंकड़ों को तैयार करते समय महाकुंभ से जुड़े डेटा को जरूर शामिल किया जाए। कहा कि आम जनता की सुविधा शीर्ष प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि हर जिले में आंगनबाड़ी का अपना भवन हो इसके लिए प्रस्ताव बनाएं। राज्य सरकार इसमें हर स्तर पर मदद करेगी। स्टार्ट-अप को चिन्हित कर उन्हें यूनिकार्न की श्रेणी में लाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। निर्देश दिए कि ऊर्जा विभाग के शीर्ष अधिकारी फील्ड में जाएं। उपभोक्ताओं से मिलें और उनकी समस्याओं का समाधान कराएं।

उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटन के सापेक्ष कम खर्च करने वाले विभागों की मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त समीक्षा करें। खर्च की स्थिति को और बेहतर करने के प्रयास किए जाएं। वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था की अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव पाक्षिक और विभागीय मंत्री बैठक कर मासिक समीक्षा करें। आवास विभाग की वे संपत्तियां जिनका विक्रय शेष है, उनके लिए नई नीति लाई जाए।

वन ट्रिलियन डालर इकोनामी की सफलता के लिए हर विभाग को अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। अपनी क्षमता को पहचानकर नए आयामों को विस्तार दें। समीक्षा बैठक में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति, अपनाई गई रणनीति और प्रभावों के हर पहलू पर विचार किया जाए और बेहतरी के लिए कार्ययोजना बनाकर लागू किया जाए।

स्वास्थ्य सेक्टर से हर व्यक्ति प्रभावित होता है। इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। मरीजों की सुविधा और डाक्टरों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाया जाए। प्रदेश में 80 मेडिकल कालेज संचालित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आम जन को सुलभ चिकित्सा सुविधा मिल सके इसके लिए मेडिकल कालेजों की नियमित मानीटरिंग की जाए। यह सुनिश्चित करें कि आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज करने वाले अस्पतालों का भुगतान एक माह से अधिक विलंबित न हो। गर्मी का मौसम प्रारंभ हो चुका है। विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में सुचारु जलापूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

सीएम के प्रस्तावित रूट पर निराश्रित पशु टहलते मिलने पर दो बेलदार निलंबित

जासं, वाराणसी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काशी दौरे में हुई लापरवाही को नगर निगम ने गंभीरता से लिया है। 12 मार्च को सीएम के प्रस्तावित रूट क्षेत्र कबीरचौरा में निराश्रित पशुओं के मिलने पर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने पशु चिकित्सा एवं कल्याण विभाग के दो नियमित कर्मचारियों (बेलदार) अमृत लाल और संजय प्रजापति को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में को निलंबित कर दिया है। आउटसोर्स के 14 कर्मियों की सेवा भी समाप्त कर दी है। नगर आयुक्त ने निराश्रित पशुओं की समस्या को लेकर पशु चिकित्सा एवं कल्याण विभाग से भविष्य में और अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि नगर में किसी वीवीआइपी आगमन के दौरान कोई असहज स्थिति उत्पन्न न हो।